



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 21, 2001/श्रावण 30, 1923

No. 225]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 21, 2001/SRAVANA 30, 1923

काणिज्य एवं उद्योग भंत्रालय

(काणिज्य विभाग)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2001

विषय : यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा और यू.एस.ए. मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 24/1/2001-डीजीएडी.—मै. जिंदल स्ट्रिप्स लि., हिसार ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा और यू.एस.ए. मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

शामिल उत्पाद: वर्तमान मामले में जांच के अधीन उत्पाद स्टेनलैस स्टील कोयल्स, शीट्स और प्लेट्स हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

स्टेनलैस स्टील के सभी ग्रेड/सीरिज के कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स, जिनकी चौड़ाई 600 मिली0 मी0 अथवा अधिक है, चाहे वे प्रसंस्कृत हैं अथवा नहीं।

स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड प्रोडक्ट्स के रूप में वर्णित सम्बद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं0 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 और 7219.90 के अंतर्गत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के मामले में बाध्यकर नहीं है।

2. घरेलू उद्योग की स्थिति: याचिकाकर्ता का कहना है कि भारत में निम्नलिखित कंपनियां सम्बद्ध वस्तुओं की उत्पादक हैं :-

- (क) मै0 जिंदल स्ट्रिप्स लि0, हिसार
- (ख) मै0 सलेम स्टील प्लांट, सलेम

मैं 0 जिंदल स्ट्रिप्स लि0, हिसार ने याचिका दायर की है और इसे इसके बाद याचिकाकर्ता कहा गया है। कुल घरेलू उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा 65.99 % बनता है और इसलिए वह वर्तमान याचिका दायर करने की पात्रता को पूरा करता है।

3. संबंधित देश: वर्तमान जांच में शामिल देश/क्षेत्र यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा तथा यूएसए हैं (जिन्हें इसके बाद सम्बद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है)।

4. समान वस्तु: याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके द्वारा उत्पादित माल यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा तथा यूएसए मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित माल के समान वस्तु है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित माल को नियमों के अर्थों के भीतर सम्बद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित माल के समान वस्तु माना जा रहा है।

5. पाटन तथा पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य:

क) यूरोपीय संघ:

याचिका में कहा गया है कि जो देश यूरोपीय संघ का एक हिस्सा हैं, उन सभी देशों में वस्तुओं का व्यापार यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच मुक्त रूप से होता है। इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की सुनिश्चित व्यवस्था के अनुसार जांच शुरू करने के मामले में समस्त यूरोपीय संघ में घरेलू कीमतों को एक समान माना गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जर्मनी इस्पात बाजार का मुख्य केन्द्र है और उनकी घरेलू बिक्री कीमतों को अन्य सदस्य देशों की घरेलू कीमतों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

अप्रैल-दिसंबर, 2000 (जांच की अवधि) के दौरान सामान्य मूल्य का परिकलन अंतर्राष्ट्रीय रेटेनलैस और एलौय मैटल्स सैक्टर में महत्वपूर्ण बाजार अनुसंधान फर्म हेन्ज एच0 परिसर एंड कं0 की वीकली फैक्स सर्विस में उपलब्ध सूचना पर आधारित है।

ख) जापान

जापान में सामान्य मूल्य एक महत्वपूर्ण प्रकाशन " दैटेक्स रिपोर्ट" से उपलब्ध सूचना पर आधारित है जिसमें जांच की अवधि के दौरान टोक्यो मार्ट में प्रचलित कीमतों का ब्यौरा दिया गया है।

ग) कनाडा:

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे कनाडा में घरेलू बाजार में प्रचलित कीमतों के बारे में सीधे दस्तावेजीय साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। तथापि, नैफटा के आगमन से यू0एस0 बाजार में कीमतों को भी कनाडा में सामान्य मूल्य के लिए पर्याप्त साक्ष्य माना जाना चाहिए। तदनुसार, जांच की

अवधि में सामान्य मूल्य का अनुमान कनाडा में सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों पर 4% की प्रचलित एमएफएन दर को ध्यान में रख कर लगाया गया है।

घ) यू०एस०ए०

अप्रैल-दिसम्बर, 2000 (जांच की अवधि) में यू०एस०ए० में सम्बद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य यू०एस०ए० में मैटल एलॉयस से संबंधित एक महत्वपूर्ण वैबसाइट www.amm.com पर उपलब्ध कीमत विवरण पर आधारित है।

निर्यात कीमत:

यांचिकाकर्ता ने कहा है कि सम्बद्ध देश सम्बद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात कीमतों पर कर रहे हैं जो उनके सामान्य मूल्य से बहुत कम हैं। औसत सी आई एफ कीमतें डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित हैं और कारखाना द्वार पर कीमतों के परिकलन के लिए इनका समायोजन किया गया है। सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमतों पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से बहुत अधिक है।

इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा तथा यू०एस०ए० में विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य उस मूल्य से बहुत अधिक है जिस पर इसे भारत को निर्यात किया गया है। इस बात से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा तथा यू०एस०ए० से निर्यातकों द्वारा सम्बद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

6. क्षति एवं कारणात्मक संबंध: घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक संकेतक जैसे उत्पादन, बिक्री, लाभ/हानि इत्यादि समग्र तथा संचयी रूप से बताते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वारस्तविक क्षति हुई है।

7. पाटनरोधी जांच की शुरुआत: उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, सम्बद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं की कथित डंपिंग होने, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।

8. जांच की अवधि: वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2000 से 31 दिसम्बर, 2000 (9 महीने) तक की है।

9. सूचना देना: संबद्ध देश में निर्यातकों और भारत में आयातकों जिनके इससे संबंधित होने की जानकारी है, को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित रूप में तथा निर्धारित ढंग से निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेज दें।

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि की सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अभिवेदन दे सकती है।

10. समय सीमा: वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों तथा आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर सूचना प्रस्तुत करनी होगी। कृपया यह नोट किया जाए कि अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने की उपर्युक्त समय-सीमा में वृद्धि करने हेतु कोई भी अनुरोध, चाहे कुछ भी हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. पाटनरोधी जांच चूंकि एक समयबद्ध कार्रवाई है, अतः यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है अथवा सूचना किसी भी प्रकार से अपूर्ण है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त नियम के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकते हैं;

12. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण: नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

13. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समयावधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

एस. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2001

Subject : Initiation of anti-dumping investigations concerning import of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel originating in or exported from European Union, Japan, Canada and USA.

No. 24/1/2001-DGAD.—M/s. Jindal Strips Ltd., Hisar, have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Cold Rolled Flat Products of stainless steel originating in or exported from European Union, Japan, Canada and USA and have requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

1. Product Involved: The product under investigation in the present case is Stainless Steel Coils, Sheets and Plates of the following description:-

“Cold rolled Flat Products of stainless steel, of a width of 600mm or more, whether further processed or not of all grades/series.”

The subject goods described as Cold rolled Flat Products of stainless steel, are classified under Customs sub-heading nos. 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 and 7219.90 of Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

2. Domestic Industry Standing: The petitioner has stated that the following companies are the producers of the subject goods in India:-

- (a) M/s Jindal Strips Ltd., Hisar;
- (b) M/s Salem Steel Plant, Salem.

M/s Jindal Strips Ltd., Hisar, has filed the petition and is hereinafter referred to as the petitioner. The petitioner accounts for 65.99% of the total domestic production and therefore satisfies the standing to file the present petition.

3. Country(ies) Involved: The countries/territory involved in the present investigations are European Union, Japan, Canada and USA (referred to as subject countries/territory hereinafter).

4. Like Goods: The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from European Union, Japan, Canada and USA. Goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles to the goods imported from the subject countries/territory within the meaning of the Rules.

5. Dumping and Dumping Margin:

Normal Value:

(A) European Union:-

The petition states that in all countries that are a part of the European Union, goods are freely tradable between the member countries of the European Union. Therefore, as per the consistent practice of the Designated Authority, the domestic prices in the entire European Union have been treated as the same for the purpose of initiation. It has also been stated in the petition that Germany is the hub for the steel market and their domestic selling prices can be accepted as domestic prices of other member countries also.

The calculation of normal value during April-December 2000 (period of investigation) is based on information available in Weekly Fax Service of HEINZ H. PARISER & Co. the leading market research firm in International Stainless and Alloy Metals Sector.

(B) Japan:-

The normal value in Japan is based on information from "The Tex Report", a leading publication indicating the prices prevailing in the Tokyo Mart in the period of investigation.

(C) Canada:-

The petitioners have stated that they were not able to get direct documentary evidence with regard to the prices prevailing in the domestic market in Canada. However with the advent of NAFTA, the prices in the US market should also be considered sufficient evidence for normal value in Canada. Accordingly, the normal value in Canada for the period of investigation has been estimated taking into consideration the prevalent MFN rate of 4% on imports of the subject goods into Canada.

(D) USA:-

The normal value for the subject goods in USA is based on price history as available with Website www.amm.com, a leading website on Metal Alloys in USA during April-December 2000 (period of investigation).

Export price:

The petitioner has stated that the subject countries are exporting the subject products into India at prices which are significantly lower than their normal values. The average cif prices are based on data published by DGCI&S and have been adjusted to arrive at the ex-works price. Considering the normal value and export prices the dumping margins are significantly higher than the de-minimis limit.

There is sufficient evidence that the normal values of the product under consideration in European Union, Japan, Canada and USA are significantly higher than the prices at which it has been exported to India, indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped by the exporters from European Union, Japan, Canada and USA.

6. Injury and Causal Link: The various economic indicators relating to domestic industry such as production, sales, profit/loss etc. collectively and cumulatively, indicates that the domestic industry has suffered injury. There is sufficient *prima facie* evidence that the imports of the product under consideration have caused material injury to the domestic industry.

7. Initiation of Anti-Dumping Investigation: In view of the foregoing paragraph, the Designated Authority initiates anti-dumping investigations to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

8. Period of Investigation: The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st April 2000 to 31st December, 2000 (9 months).

9. **Submission of Information:** The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Directorate of Anti-Dumping, Udyog Bhavan, New-Delhi -110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

10. **Time Limit:** Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately. It may kindly be noted that no requests whatsoever shall be entertained for extension of the above-stated time limit for submission of the required information.

11. Anti-dumping investigations being a time bound exercise, the Designated Authority may record its findings on the basis of facts available on record in accordance with the Rules supra, if no response is received within the time stipulated or the information is incomplete in any respect.

12. **Inspection of Public File:** In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

13. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

